



चक्रवाती तूफान “बिपरजॉय” शुक्रवार दोपहर बाद राजस्थान में प्रवेश करेगा। तूफान आने से 36 घंटे पहले ही इसका असर प्रदेश के कई इलाकों में दिखने लगा है। गुरुवार को राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई, वहीं कुछ जगहों पर बादल छाए रहे। मौसम विभाग का कहना है कि, प्रदेश में तूफान कुछ कमजोर होकर (डीप डिप्रेशन में बदलकर) प्रवेश करेगा। इसका असर 19 जून तक बना रहेगा तथा सर्वाधिक असर 17 जून को रहने के आसार हैं। उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, वृरू व आस-पास के कुछ जिलों में तूफान का असर अपेक्षाकृत कम रहेगा। वहीं ज्यादातर जिलों में अलग-अलग समय पर तूफान का असर रहेगा। जोधपुर, जालौर, बाड़मेर व पाली में तूफान का सर्वाधिक असर रहने की आशंका है। वहीं राज्य सरकार ने आपदा राहत के लिए टीमें तैनात कर दी हैं।

दिल्ली में सुलह वार्ता के बाद पायलट खेमे के नेता का गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ा बयान

गहलोत सरकार के सैनिक कल्याण मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा, जो मुखर पायलट समर्थक हैं, ने कहा कि, नौजवानों की सुध नहीं ली तो सरकार आना नामुमकिन है

झुंझुं, 15 जून (निसं)। झुंझुं के उदयपुरवाटी से विशाख एवं सैनिक कल्याण मंत्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा ने अपने बयान से अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आर.पी.एस.सी. पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि, आर.पी.एस.सी. के रवैये और खराब ढांचे के कारण नौकरी की आस देख रहे युवा अपनी जान दे रहे हैं।

उदयपुरवाटी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजेन्द्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि, राजस्थान का नौजवान परेशान है। उदयपुरवाटी विधानसभा में दो महलों में 30 युवाओं ने जान दे दी है। सुसाइड केवल बेरोजगारी के कारण हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि, हमारी सरकार चाहे बी.पी.एल., चुबुगों, दिव्यांगों, बीमारों के लिए कुछ भी करे, लेकिन, नौजवानों के लिए भी करना चाहिए। हर बेरोजगार को 20 हजार

■ गुढ़ा ने कहा, “नौजवान दस-दस साल तैयारी करता है पर पेपर लीक और इंटरव्यू सिस्टम से हार जाता है। अब तो इन नौजवानों को देखकर डर लगता है, क्योंकि अगले चुनाव में यही फैसला करेंगे।”

■ गुढ़ा ने दावा किया, उनके चुनाव क्षेत्र में गत दो माह में बेरोजगारी के कारण 30 युवाओं ने जान दी है।

■ उन्होंने कहा, सरकार गरीबों, बीमारों, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए चाहे जो करे पर नौजवानों की भी सुध ले, उन्हें प्रति माह 20,000 रु. बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए।

रूपए मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए।

उन्होंने इस मौके पर कहा कि, रोज पेपर लीक हो जाते हैं, आर.पी.एस.सी. सदस्य और बाकी लोगों के बारे में सब जानते हैं। सचिन पायलट ने आर.पी.एस.सी. पुर्नगठन की बात कही है। पायलट ने कहा है कि, दो-तीन साल तक नौजवान नौकरी के लिए भटकता है और फिर पेपर लीक हो

जाते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10-10 साल तक नौजवान कॉम्पटीशन की तैयारी करता है, नौकरी की आस रखता है, फिर पेपर लीक और इंटरव्यू सिस्टम से हार जाता है। इसलिए आर.पी.एस.सी. के रवैये और खराब ढांचे के कारण युवा सुसाइड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि, आने वाले चुनावों में 18 से 36 साल के युवा चुनाव का फैसला करेंगे। यदि

नौजवानों की परेशानियों को दूर नहीं किया तो आने वाले समय में सभी को पता चल जाएगा।

गुढ़ा ने कहा कि, युवा कॉम्पटीशन की तैयारी में बैंग लटकाए घूमते हैं, जब भी उन्हें देखते हैं तो डर लगता है। क्योंकि सरकार के खिलाफ वे गुस्से में हैं और सरकार बनाने का फैसला वो ही करने वाले हैं।

कहा जा रहा है कि, गुढ़ा इन दिनों

‘हिंसा प्रस्त ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कूकी आदिवासियों को खत्म करने के साम्प्रदायिक एजेंडा पर चल रहे हैं। आई.ए. में कहा गया है कि सशस्त्र साम्प्रदायिक संगठन कूकी आदिवासियों का सफाया कर रहे हैं। उन्होंने अदालत से प्रार्थना की कि भारतीय सेना के माध्यम से इस जनजाति को संरक्षण प्रदान किया जाये क्योंकि सरकार और उसकी पुलिस से आदिवासियों का विश्वास उठ गया है। संगठन ने दलील दी कि पिछली सुनवाई में, सांलिंसिटर जनरल द्वारा दिये गये आश्वासनों के बावजूद, अभी तक कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। फोरम ने आई.ए. में कहा है कि, “इन आश्वासनों के दिये जाने के बाद, 81 कूकी आदिवासी मार दिये गये, 237 चर्च तथा 73 प्रशासकीय भवन/क्वार्टर जला दिये गये, 141 गाँव तबाह कर दिये गये तथा 31,410 कूकी अपने घरों से दूसरी जगह चले गए। अब सत्ता के आश्वासन किसी काम के नहीं रहे हैं। ये आश्वासन नितांत गैर गंभीर है, तथा इनकी क्रियान्विति तो सरकार का उद्देश्य ही नहीं है। फोरम ने केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों को लेकर भी निराशा प्रकट की।

एक साल में चीन में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आज भी है। युवा वर्ग कह रहा है कि उनकी पीढ़ी आखिरी है। वे स्वतंत्र समाज में नहीं रह सकते हैं। ये युवा लोग ऐसे प्रतिबंधित समाज में अपने बच्चों का पालन-पोषण नहीं करना चाहते हैं। युवा महिलाओं के शादी से विमुख होने का एक बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि पारम्परिक चीनी समाज में अभी भी महिलाओं से एक आज्ञाकारी पत्नी की भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है और युवा महिलाएं इसे सहने को तैयार नहीं हैं। वे अविवाहित रह कर करियर और नए अवसर तलाश करना ज्यादा पसंद करती हैं।

चीन के आर्थिक विकास के कारण महिलाओं के लिए भी करियर के नए दरवाजे खुल गए हैं। इस तरह की नौकरियों से उन्हें ऐसा आरामदायक जीवन जीने का

अवसर मिलता है जिसमें पारिवारिक मांगों के आगे सिर झुकाने की जरूरत नहीं होती है। चीन के समाज में स्त्री-पुरुष के भेद में तेजी से कमी आई है। युवा महिलाएं अपने को ज्यादा सशक्त महसूस करने लगी हैं। लेकिन इन सभी सामाजिक परिवर्तनों को देखते तो इस बात से इंकार नहीं है कि बढ़ती युवा बेरोजगारी की वजह से ये बदलाव हो रहे हैं।

शादी में कमी आने का बड़ा कारण है युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी जो 20 प्रतिशत हो गई है। इसके अलावा उपलब्ध रोजगार और उससे जुड़ी आकांक्षाओं में भी भारी अंतर है। भारी बेरोजगारी का असर कई क्षेत्रों में दिख रहा है, इसका एक असर है धर्म के प्रति बढ़ता रुझान। खबरें हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग बौद्ध वताओ मंदिरों में जा रहे हैं तथा करियर व अच्छे भविष्य करने के सबसे आम उदाहरण थे:

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है बाजारों के 4700 यात्रियों के सर्वे में पता चला कि 87 प्रतिशत यात्री मानते हैं कि हवाई यात्रा क्रिटिकल है और हमें हवाई यात्रा यात्रा का ऐसा तरीका ढूंढना होगा कि यात्रा बिना बाधा के पूरी हो, सर्वे में शामिल 88 प्रतिशत ने माना कि यू.एन. के सतत विकास लक्ष्यों में उड़ान का महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वे के अनुसार 91 प्रतिशत हवाई यात्रा को आधुनिक जरूरत मानते हैं और 81 प्रतिशत यात्री महामारी से पूर्व के हवाई यात्रा करने की सुविधा दिए जाने की सलाह करते हैं।

मास्क की अनिवार्यता खत्म होने के बाद यात्रियों की बात नहीं मानने की घटनाएं कम हो गई थीं पर वर्ष 2022 में ऐसी घटनाओं में फिर से वृद्धि हुई है। अवज्ञा करने के सबसे आम उदाहरण थे:

* सिगरेट, ई सिगरेट, पफस, वेपर का केबिन या शौचालय में इस्तेमाल।
* निर्देश दिए जाने पर भी सीट बेल्ट बांधने में भी देरी करना।
* जरूरत से ज्यादा सामान ले जाना या आवश्यकता पड़ने पर सामान स्टोर नहीं करवाना।
* विमान में शराब पीना।

आई.ए.टी.ए. कहता है कि, उड़दं व्यवहार के प्रति ज़िरो टॉलरेंस की जरूरत है और इसके लिए एक “टू पिलर” रणनीति है। इसे ऐसी घटनाओं की वृद्धि रोकने की कायदे कानून बनाए गए हैं। इसमें सरकारों से आश्वासन लिया जाता है कि वे उड़दं यात्रियों पर कानूनी कार्यवाही करेंगे चाहे वे यात्री कहीं के भी हों। इसके लिए शक्तियां भी दी गई हैं। ऐसे अधिकारी एम.पी. 14 में हैं और आई.ए.टी.ए. का सभी देशों से आग्रह है कि इसे जल्द से जल्द मान्यता प्रदान करें। अभी तक 45 देशों ने इसे स्वीकार किया है। विश्व का 33 प्रतिशत हवाई यातायात इन देशों से संबंधित है।

बंगाल में चुनाव आते ही फिर खूनी दौर शुरु !

बंगाल में पंचायत चुनाव नामांकन के आखिरी दिन चार लोगों की गोली मारकर सरेंआम हत्या

कोलकाता, 15 जून। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन गुरुवार को राज्य के कुछ जिलों में हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई, जिसमें कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। इसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने चुनाव खत्म होने तक पूरे राज्य में केंद्रीय सुरक्षाबलों की तैनाती का आदेश दिया है।

राज्य चुनाव आयोग (एस.ई.सी.) पर कड़ी टिप्पणी करते हुए, मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणम और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने 48 घंटे के भीतर केंद्र से अर्धसैनिक बल बटालियन मांगने और उन्हें राज्य के हर हिस्से में तैनात करने को कहा, न कि, केवल उन सात जिलों को जिन्हें पहले संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया था। सिर्फ सात जिलों को

■ कोलकाता हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुये राज्य में पुलिस बलों को हटाकर तुरंत केन्द्रीय सुरक्षाबलों की तैनाती के आदेश दिये

■ प. बंगाल के माकपा सचिव सलीम मोहम्मद ने आरोप लगाया कि, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने हमारी पार्टी के एक उम्मीदवार के साथ नामांकन दाखिल करने जा रहे तीन कार्यकर्ताओं को गोली मार दी।

पहले संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया था। ये जिले बीरभूम, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली, मुर्शिदाबाद, पूर्वी मिदनापुर और जलपाईगुड़ी हैं।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक पंचायत चुनाव के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवारों का एक समूह नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए बी.डी.ओ. कार्यालय की ओर जा

रहे थे। इसी दौरान कुछ हमलावरों ने तीन से चार लोगों को गोली मार दी, इन्हीं में से कई लोगों की मौत हो गई। प्रदेश माकपा सचिव मोहम्मद सलीम ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार और समर्थक नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे थे तभी तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। उन्होंने आरोप लगाया कि, पश्चिम बंगाल पुलिस का एक वर्ग अभी भी

तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के साथ सहयोग कर रहा है और प्रदेश चुनाव आयोग गैर-जिम्मेदार बना हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि ममता सरकार को उसके प्रशासन के गैर-जिम्मेदाराना और एक्तरफा रवैये की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

गौरतलब है कि, गत 13 जून को मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने एस.ई.सी. को हिंसा और आशंका के महेनजर कानून और व्यवस्था की स्थिति का मूल्यांकन करने और संवेदनशील जिलों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में हिंसा देखने वाले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का आदेश दिया था। गुरुवार को एस.ई.सी. ने मुख्य न्यायाधीश की पीठ से केंद्रीय बल की तैनाती पर अपने आदेश पर पुनर्विचार करने की अपील की।

गुजरात भाजपा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुनावों में प्रमुख राज्यों का चुनाव प्रबंधन देखने के लिए चुना है। इनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र वाराणसी के माइक्रो मैनेजमेंट में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उसी दौरान मोदी की उन पर नजर पड़ी थी।

संभावना है कि मोदी की इच्छानुसार उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जा सकता है। उनका गुजरात में शानदार रिकॉर्ड है जहां पार्टी ने 182 में से 156 सीटें जीती थीं और जो प्रतियोगी भी 49 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया।

मोदी ने खुद पाटिल की प्रशंसा की और भाजपा नेताओं व सांसदों से कहा कि अन्य राज्यों में चुनाव रणनीति बनाने के लिए पाटिल मॉडल अपनाएं।

मोदी की गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष से चर्चा के बाद निर्णय लिया गया है कि यूपी ही नहीं बल्कि मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों का चुनाव प्रबंधन पाटिल को सौंपा जाए।

पाटिल मोदी की उच्चस्तरीय टीम में शामिल हो सकते हैं और पार्टी को चुनाव अभियान देखने के लिए उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है।

गुजरात तट से टकराया सायक्लोन बिपरजॉय, 125 कि.मी. की रफ्तार से हवायें चली

आठ राज्यों में अलर्ट जारी किया गया, गुजरात में सायक्लोन के कारण पेड़ व बिजली के पोल उखड़े, कई इलाकों में बिजली काटी गई

नई दिल्ली, 15 जून। सायक्लोन बिपरजॉय गुरुवार शाम को गुजरात पहुंच चुका है। सौराष्ट्र तट पर सायक्लोन का लैंडफॉल भी शुरू हो चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि, आधी रात तक लैंडफॉल प्रक्रिया जारी रहेगी। सायक्लोन के कारण गुजरात के तटीय इलाकों में बेहद तेज हवाएं चलनी शुरु हो गईं। गुजरात (कच्छ) के तटीय इलाकों से एक लाख लोगों को तट के किनारे से निकाल सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। साबरमती रिवर फ्रंट और द्वारकाधीश मंदिर को बंद कर दिया गया। यह सायक्लोन कच्छ और पाकिस्तान के सिंध के तट से टकराएगा। बीते 60 सालों में यह तीसरा

■ गुजरात (कच्छ) के तटीय इलाकों से एक लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है।

■ सायक्लोन बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए, केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक, सब अलर्ट मोड पर हैं। गुजरात में एन.डी.आर.एफ. की 17 टीमें और एस.डी.आर.एफ. की 12 टीमें तैनात हैं। वहीं, नौसेना के 4 जहाज स्टैंडबाय पर रखे गए हैं।

तूफान है, सायक्लोन बिपरजॉय जैसे- जैसे आगे बढ़ रहा है, इसका असर तेज होता दिखने दे रहा है। सायक्लोन बिपरजॉय के 15 जून से तबाही मचाने की आशंका के बीच 8 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। नेवै, एयरफोर्स सेना, एन.डी.आर.एफ. समेत तमाम

सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।

सायक्लोन के कारण कच्छ के तटीय इलाकों में 115-125 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। गुरुवार शाम को सौराष्ट्र के सभी इलाकों में भारी बारिश भी हुई। मौसम

घबराइये नहीं, हवाई यात्रा के दौरान...

जमौन पर, जैसे हवाई अड्डों, बार रेस्त्रॉ, व ड्यूटी फ्री दुकानों पर, औद्योगिक पार्टनर्स के सहयोग से उड़दं व्यवहार के दुष्प्रणिणम पर जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। आई.ए.टी.ए. केबिन क्रू को इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। इसने 2022 के आरंभ में नए निर्देश जारी किए थे और विभिन्न एयरलाइन्स में इन घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रयुक्त तौर तरीकों की जानकारी जुटाई और जन जागरूकता पर सरकारों की व्यवसायिक समायोजन बनाए जैसे तुरंत जुमाना करना आदि।

क्लिफर्ट ने कहा कि उड़दंता की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकारें व उद्योग ज्यादा गंभीर कदम उठा रहे हैं। अधिकांश देश एम.पी. 14 को मान्यता दे रहे हैं और स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि अब सरकारें उड़दंता लोगों पर मुकदमा चलाने को तत्पर हैं।

उद्योगों के स्तर पर भी ज्यादा सहयोग

की जरूरत है क्योंकि दुर्घटनाओं की अधिकांश घटनाएं उड़ान से पहले शराब पीने से होती हैं। एयरपोर्ट की बार व रेस्त्रॉ की मदद से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि यात्री ज्यादा शराब न लें। क्लिफर्ट ने कहा कि कोई भी यात्रियों को मौज मजा करने से रोकना नहीं चाहता पर हम सब की जिम्मेवारी है कि वे अन्य यात्रियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो। बहुत के लिए हम ऐसे चंद यात्रियों पर कार्यवाही करने से नहीं हिचकेंगे जो हर किसी के लिए परेशानी पैदा करते हैं।

राहुल गांधी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उचित खाका उपलब्ध नहीं है। खड्डो टीम, 2024 बनाना चाहते हैं लेकिन गांधी परिवार की सहमति/स्वीकृति के बिना ऐसा करना मुश्किल है। कुल मिलाकर, राहुल के विदेश से लौटने पर ही कुछ जवाब मिल सकते हैं।

यूनिफॉर्म सिविल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने ही की थी, ने “कन्सल्टेशन पेपर ऑन रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ” के पृष्ठ 182 पैरा 1.15 में स्वयं ही उपरोक्त बात कही थी। आयोग ने अपनी यह रिपोर्ट 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत की थी।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आगे कहा, “जहां भारतीय संस्कृति की विविधता का गुणगान किया जाना चाहिये, वहीं समाज के विशिष्ट या कमजोर वर्गों से उनके विशेषाधिकार व संक्रिया से छीने नहीं जाने चाहिये। इस दृढ़ के समाधान का अर्थ सभी अन्तर्गों को समाप्त कर देना नहीं है।

इसीलिये उस आयोग ने समान नागरिक संहिता, जो इस स्थिति में न तो आवश्यक है और न वांछनीय, उपलब्ध कराने के बजाय, उन कानूनों पर विचार करना उचित समझा था, जो भेदभावपूर्ण हैं। ज्यादातर देश अब

अन्तर को मान्यता देने की दिशा में बढ़ रहे हैं तथा अन्तर्ग के अस्तित्व मात्र का अर्थ भेदभाव नहीं होता है, बल्कि ये तो सुदृढ़ लोकतंत्र के परिचायक होते हैं। “विधि आयोग ने पिछले दशकों में राष्ट्रीय महत्व के अनगिनत मुद्दों पर ईर्ष्या करने योग्य काम किया है।

इस (आयोग का) को उस विरासत को ध्यान में रखना चाहिये तथा याद रखना चाहिये कि राष्ट्र का हित भाजपा की राजनैतिक महत्वकांक्षाओं से प्रथक चीज है। 22वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बुधवार को एक नोटिस जारी करके इस विषय पर जनात एवं धार्मिक संगठनों के विचार मांगे हैं। नोटिस में कहा गया है कि न वांछनीय, उपलब्ध कराने के बजाय, उन कानूनों पर विचार करना उचित समझा था, जो भेदभावपूर्ण हैं। ज्यादातर देश अब